

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 187/2014/भरतपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त-"अ", भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी गोपालगढ पहाडी।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री सी.बी.अग्रवाल,
अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक : 08.02.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-"अ", भरतपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2013, जो अपील संख्या 50/उपा-भरत/2012-13 के संबंध में है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने आरोपित कर रु.6090/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण में अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों के आलोक में, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत माल "सीमेंट" के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को विक्रय के पश्चात् (एक्स पोस्ट फेक्टो) प्राप्त होना अवधारित कर, इस संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन रु 4,86,364/- को विक्रय मूल्य का भाग मानकर, घोषित विक्रयावर्त में वृद्धि कर, इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रु.6090/- आरोपित कर, वसूली योग्य होना कायम की गयी । जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा कायम उपर्युक्त वर्णित मांग राशि को विधिसम्मत नहीं होना अवधारित कर, जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 20.06.2013 के अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

✓

अपील संख्या - 187/2014/भरतपुर

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार कर, कायम की गयी मांग को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में अधिनियम की धारा 2(36) व धारा 2(41) के प्रावधानों को समझने में प्रथम दृष्ट्या विधिक भूल की है जैसाकि उनके द्वारा कय किये गये माल के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को आधार बनाकर यह निष्कर्ष अवधारित करना कि उसके द्वारा कम लाभ पर माल का विक्रय किया गया है तथा उक्त आधार पर विक्रय मूल्य में कय के पश्चात् प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को जोड़कर, विक्रय मूल्य में वृद्धि करना किसी भी रूप में विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, न ही कय के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को विक्रय मूल्य में ही अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय के प्रकाश में, जोड़ा जा सकता है । तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत समस्त माल पर विक्रेता व्यवहारी द्वारा राज्य में स्थित डिपोज़ से प्रथम बिन्दु पर, सम्पूर्ण घोषित विक्रय कीमत पर देय कर (वैट) जमा कराया गया है । विक्रेता व्यवहारी द्वारा घोषित विक्रय कीमत में से कोई रिबेट अथवा डिस्काउंट/कमीशन को कम किया जाकर, कर (वैट) का भुगतान नहीं किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में, इस आधार पर मनमर्जी से विक्रयावर्त में वृद्धि कर, करारोपण करना विधिअनुकूल नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में पुनः अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों को प्रोद्धरित कर, आरोपित कर, के बिन्दु पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया । उक्त प्रावधानों का मूल पाठ इस प्रकार है:-
अधिनियम की धारा 2(36).-“sale price” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer

HT

in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I..... **Explanation II**.- Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

अधिनियम की धारा 2(41).“turnover” means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub-section (2) of section 4 “but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;


7. उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने क्रीत माल पर, प्रथम विक्रेता व्यवहारी से डिस्काउन्ट प्राप्त किया है एवम् जिस पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय के प्रावधान लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने घोषित विक्रय कीमत में से विक्रय के पश्चात्, किसी प्रकार का कोई डिस्काउन्ट/ रिबेट/कमीशन/रिवार्ड प्रदान नहीं किया गया है । अधिनियम की धारा 2(36) में विक्रय के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त राशि की अवधारणा को परिभाषित कर, स्पष्टीकरण में वर्णित उक्त प्रावधानों अग्रिम रूप से स्पष्ट किया गया है । चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय पर डिस्काउन्ट/कमीशन प्राप्त किया गया है, परन्तु प्रथम विक्रेता व्यवहारी द्वारा इसे घोषित कर योग्य विक्रयावर्त में से कम नहीं किया गया है । अतः कम लाभ की दर के आधार पर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषित विक्रय कीमत को मनमर्जी से बढ़ाया जाकर, करारोपण



लगातार.....4

करना विधि के उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में, अनज्ञेय नहीं है। विवादित अवधि अधिनियम की धारा 18(3A) के प्रतिस्थापन दिनांक 09.03.2011 से पूर्व की है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में आगत कर, निर्गत कर से अधिक नहीं दिया जा सकता है। अतः उक्त अवधि हेतु राजस्थान कर बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स आर.एस.टायर हाउस अलवर (2013), 35 टैक्स पृष्ठ 28 तथा मैसर्स हिंगड ट्रेडर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 के प्रकरण में दिये गये निर्णय तथा उपरोक्त विवेचन के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई न्यायसम्मत औचित्य नहीं है। फलस्वरूप, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय प्रसारित किया गया।


8.2.2016
(मदन लाल)
सदस्य